

भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। [UPSC 2024]

What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.

खाद्य मुद्रास्फीति का अर्थ है उपभोक्ता टोकरी में शामिल विभिन्न खाद्य पदार्थों (जैसे—अनाज, दालें, सब्जियाँ, फल, दूध, और खाद्य तेल) की औसत कीमतों में होने वाली निरंतर एवं सामान्य वृद्धि। जब खाद्य वस्तुओं की मांग की तुलना में उनकी आपूर्ति कम हो जाती है या उत्पादन व वितरण लागत बढ़ जाती है, तो खाद्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार **लगभग 45.86%** है, जिसके कारण खाद्य वस्तुओं के दामों में मामूली वृद्धि भी देश की समग्र मुद्रास्फीति और आम परिवारों के बजट को सीधे प्रभावित करती है।

- **वर्ष 2024 की स्थिति:** मध्य-2024 में अनिश्चित मौसम, एल-नीनो के प्रभाव और सब्जियों (टमाटर, प्याज, आलू) के दामों में उछाल के कारण खाद्य मुद्रास्फीति **9% के पार** पहुँच गई थी, जिसने नीति निर्माताओं के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी कर दी थी।

1. निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण

(A) आपूर्ति-पक्षीय कारक

- **मौसम संबंधी आघात और जलवायु परिवर्तन:** अनिश्चित और विषम मौसमी घटनाएँ (जैसे एल-नीनो/El Niño के कारण कम वर्षा, अत्यधिक गर्मी और अचानक बेमौसम बारिश) फसलों की उपज को भारी नुकसान पहुँचाती हैं। मानसून सामान्य रहने के बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन और फसल-विशेष विफलताएँ बनी रहती हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढाँचे में बाधाएँ:**
 - बाढ़ और मूसलाधार बारिश से परिवहन एवं रसद प्रभावित होती है, जिससे अस्थायी मूल्य वृद्धि होती है।
 - कोल्ड-स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की कमी के कारण विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं (टमाटर, प्याज, आलू जैसी सब्जियों) का भारी मात्रा में नुकसान होता है।
- **लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति:** उर्वरक, बीज, कीटनाशक और डीजल (ईंधन) की बढ़ती कीमतों से कृषि उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिसका अंतिम बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता:** दालों और खाद्य तेलों के मामले में भारत का आयात पर अत्यधिक निर्भर रहना घरेलू कीमतों को वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाता है।

(B) मांग-पक्षीय एवं संरचनात्मक कारक

- **आय वृद्धि और आहार प्रतिरूप में बदलाव:** बढ़ती आय, तेजी से होते शहरीकरण और मध्यम वर्ग की वृद्धि के कारण कार्बोहाइड्रेट आधारित भोजन की तुलना में प्रोटीन-समृद्ध खाद्य पदार्थों (दूध, फल, सब्जियां, अंडे, मांस) की मांग बढ़ी है, जिसकी आपूर्ति उस गति से समायोजित नहीं हो पाती।
- **बाजार की अक्षमताएँ:** APMC मंडियों में बिचौलियों की लंबी श्रृंखला, उच्च कार्टेलाइजेशन और पारदर्शिता की कमी के कारण खेत-दर और खुदरा कीमतों के बीच बहुत बड़ा अंतर आ जाता है।
- **घरेलू भंडारण और जमाखोरी:** प्रमुख फसलों के मौसम के दौरान व्यापारियों द्वारा की जाने वाली कृत्रिम जमाखोरी और बाजार की सट्टेबाजी कीमतों में अचानक उछाल लाती है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि:** MSP में की जाने वाली निरंतर वृद्धि से किसानों के लिए एक न्यूनतम मूल्य-तल तय हो जाता है, जो बाजार में खाद्य अनाजों की समग्र मूल्य बेंचमार्क को ऊपर धकेलता है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता



(A) मौद्रिक नीति की सफलता एवं शक्तियाँ

- **मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का अंकुश:** RBI का 'लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' (FIT - $4\% \pm 2\%$) और रेपो दर समायोजन द्वितीयक प्रभावों को रोकने में मदद करता है, जिससे गैर-खाद्य (कोर) मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है।
- **मांग नियंत्रण:** उच्च ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में कुल मांग और तरलता को संतुलित करती हैं, जिससे खाद्य कीमतों में हो रही वृद्धि का असर अन्य क्षेत्रों में फैलने से रुकता है।
- **हालिया स्थिरता:** 2024 में रेपो दरों को सख्त बनाए रखने और राजकोषीय कदमों के तालमेल से 2025 की शुरुआत में खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली।

(B) मौद्रिक नीति की सीमाएं एवं चुनौतियाँ

- **आपूर्ति-पक्षीय झटकों पर अप्रभावी:** मौद्रिक नीति मुख्य रूप से मांग-जनित मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा सकती है। यह खराब मौसम, फसल विफलता या रसद बाधाओं जैसे आपूर्ति-पक्षीय झटकों को ठीक नहीं कर सकती।
- **संचरण में समय:** नीतिगत दरों में परिवर्तन का वास्तविक अर्थव्यवस्था और खुदरा कीमतों पर असर दिखने में 3 से 6 महीने का समय लगता है।
- **निर्माताओं के लिए लागत वृद्धि:** उच्च ब्याज दरों से किसानों और खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए कार्यशील पूंजी महंगी हो जाती है, जो विडंबनापूर्ण रूप से उत्पादन लागत को और बढ़ा सकती है।
- **गैर-खाद्य मांग पर अनुचित दबाव:** केवल खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दरें बढ़ाने से अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों (जैसे निर्माण, उपभोक्ता वस्तुएं) की विकास दर धीमी होने का जोखिम रहता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

यद्यपि RBI की मौद्रिक नीति समग्र मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किंतु **भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या बुनियादी रूप से आपूर्ति-पक्ष और संरचनात्मक चुनौतियों में निहित है।** केवल मौद्रिक नीति के बल पर खाद्य मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से हल नहीं किया जा सकता।

दीर्घकालिक समाधान के लिए निम्नलिखित **बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:**

1. **सप्लाई चेन सुधार:** e-NAM का पूर्ण कार्यान्वयन, APMC सुधार और खेत से बाजार तक कोल्ड-चैन नेटवर्क को मजबूत करना।

2. **जलवायु-सक्षम कृषि:** सूखा और बाढ़-प्रतिरोधी बीजों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा सूक्ष्म सिंचाई को विस्तार देना।
3. **आयात विविधीकरण एवं आत्मनिर्भरता:** 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन' और दालों के उत्पादन प्रोत्साहन जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करना।
4. **राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति का समन्वय:** समयबद्ध तरीके से बफर स्टॉक जारी करना, निर्यात-आयात शुल्कों में लचीलापन और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी उपयोग।

